नगरीकरण को अनेक अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में ग्रामीण समाज का शहरी वातावरण में परिवर्तित होना या ग्रामीणों द्वारा नगरी मूल्यों का अपनाया जाना नगरीकरण माना जाता है। भूगोल के क्षेत्र में प्राकृतिक वातावरण का शहरी वातावरण में बदलना एवं नये शहरों की उत्पत्ति को नगरीकरण कहा जाता है।

भारत में 2001 की जनगणना में नगरी क्षेत्र को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है —

- वे सभी स्थान जहाँ नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या नोटीफाइड टाउन एरिया क्षेत्र हो।
- वे सभी स्थान जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं —

(a) कम-से-कम 5000 जनसंख्या हो।
(b) पुरुष कार्यकारी जनसंख्या 75% या कृषि एवं व्यवसायों में लगा हो।
(c) जनसंख्या कम-से-कम 400 प्रतिवर्ग किलोमीटर हो।

भारत में नागरीकरण की प्रवृत्तियाँ

यद्यपि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, तथापि स्वतंत्रता के बाद से इस प्रवृत्ति में कुछ बदलाव देखने को मिला है। धीरे-धीरे देश की शहरी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 1901 में शहरी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का केवल 10.8% थी, जो स्वतंत्रता के बाद 1951 में 17.3%, 2001 में यह बढ़कर 27.8% हो गई। इससे यह स्पष्ट है की नगरीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही है।

ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या : आर्थिक विकास के कारण अर्थव्यवस्था का स्वरूप कृषक से परिवर्तित होकर अंततः औद्योगिक हो जाता है। और औद्योगीकरण में वृद्धि के परिणामस्वरूप जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक केन्द्रों की ओर स्थानांतरित होने लगती है। 1921 में जनसंख्या का 11.2% भाग शहरों में निवास करता था 2001 में बढ़कर 28% हो जाता।

Scanned with CamScanner

नगरीय जनसंख्या का राज्यवार वितरण भारत क्षेत्र और जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से एक बहुत बड़ा देश है। इसकी अनेक राज्य विश्व के अधिकांश देशों से सिर्फ क्षेत्रफल में ही नहीं बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़े हैं। 1951-61 के दशक में उत्तर-प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में शहरी जनसंख्या में वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से नीची थी, लेकिन कालान्तर में इन राज्यों में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है।

भारत में नगरों के आकार के आधार पर संख्या और श्रेणियाँ :- भारत में प्रथम श्रेणी में आने वाले शहरों में ही शहरी जनसंख्या का केन्द्रीकरण है। 1951 में प्रथम श्रेणी के शहरों की कुल संख्या 44.6% रहता था 2001 में शहरी जनसंख्या की 62.7% हो गई।

द्वितीय श्रेणी के नगरों की संख्या जो 1951 में 91 थी, वह 2001 में बढ़कर 498 हो गई।

तृतीय श्रेणी के नगरों की संख्या जो 1951 में 330 थी, वह 2001 में बढ़कर 1386 हो गई।

चतुर्थ श्रेणी के नगरों की संख्या 608 थी, जो 2001 में बढ़कर 1580 हो गई।

पंचम श्रेणी के नगरों की संख्या 1951 में 1,124 थी, जो 2001 में गिरकर 1057 हो गई।

षष्ठ श्रेणी के नगरों की 1951 की 1951 में 564 थी, जो 2001 में गिरकर 227 हो गई।

10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगर :- 1951 की जनगणना के अनुसार देश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों की संख्या 4 थी, जो 1961 में बढ़कर 6 हो गई। इसी प्रकार 1971 में जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों की संख्या 9 थी जो 1981 में बढ़कर 12 हो गई। 2001 की जनसंख्या के अनुसार 50 लाख के ऊपर आबादी वाले 35 बड़े नगरों में लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली देश के तीन महानगरों

Scanned with CamScanner

में देश की जनसंख्या का 4% से भी अधिक भाग केन्द्रित है।

2001 की जनगणना के अनुसार स्लम जनसंख्या वाले शहर

2001 की जनगणना में 605 ऐसे शहर लिए गए जहाँ स्लम क्षेत्र मौजूद है। स्लम क्षेत्र की मौजूदगी वाले शहरों की जनसंख्या नगरों की कुल जनसंख्या का 25.58% थी। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या महावल्ट्र (22.58%) दर्ज की गयी है। जबकी न्यूनतम (0.25%) पटना में रिकार्ड किया गया है। स्लम जनसंख्या में साक्षरता काफी ऊँची पायी गयी जो 88.08% (मेघालय) 55.46 (चण्डीगढ़) में रही।

नगरीकरण के खतरे एंव चुनौतियां

नगरीकरण को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है किंतु तेजी से बढ़ते हुए नगरीकरण से महानगरों में तरह-तरह की समस्याएँ पैदा हो सकती है। जो नगरीय जन जीवन के लिए जटिलताओं को बढ़ा सकता है। तीव्र नगरीकरण के साथ नगरीय सुविधाओं में तीव्र नहीं हो पाती है। इन परिस्थितियों में शहरों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक समस्याओं को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं अतिरिक्त जीवन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे - स्थान, आवास, रोजगार, विद्युत एंव जल आपूर्ति, परिवहन शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य एंव अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का अभाव सकंट की स्थिति उत्पन्न कर सकती है।

शहरों पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव पर चिन्ता जताते हुए रिपोर्ट में यह आकलन करने की कोशिश की गई है कि शहरी क्षेत्र किस हद तक इस दबाव को झेल सकेंगे। इस रिपोर्ट में तीव्र नगरीकरण के कारण, शहरों में बिजली, पानी, परिवहन सेवा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले दबावों के अतिरिक्त ट्रैफिक जाम तथा वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण जैसे विकराल समस्याओं से निबटने के लिए शहरों के संतुलित विकास पर जोर दिया गया है।

Scanned with CamScanner